एकता परिषद
राहत अभियान

2-6 मई 2020
संस्करण क्रमांक - 9

भूमिहीनों एवं असंगठित मजदूरों की बेपटरी हुई आजीविका

मजदूरों की आजीविका को सामान्य स्थिति आने में लगेगा एक साल

- रवीन्द्र सक्सैना,ग्वालियर

कोरोना वायरस महामारी के दौर में पूरे देश में पिछले 40 दिन से चल रहे लॉकडाउन ने देश के 14 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति को बेपटरी कर दिया है। जहां एक तरफ मजदूरों में घर वापसी के लिए भागदौड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ इतने दिन के बाद केंद्र सरकार तथा छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले उद्योगपतियों के समझ में आया है कि यह सभी मजदूर जाने के बाद उनके उद्योग भी सामान्य तरीके से प्रारंभ नहीं हो पाएंगे। इसका प्रभाव आगे आने वाले कुछ महीनों में दिखाई देगा इसलिए काफी देर से अब उद्योगपति तथा सरकार मजदूरों को समझाने तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के आश्वासन देने में लगी है, जबकि लॉकडाउन के 2 सप्ताह तक मजदूरों की किसी ने भी सुधबुध नहीं ली, ऊपर से प्रचार-प्रसार इतना अधिक था कि लोगों के अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो गई । इसलिए किसी भी तरह लंबी लंबी दूरी तय करके प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य में लौटने लगे।

निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे देश में सभी क्षेत्रों में पड़ा है जहां एक तरफ छोटे–छोटे उत्पादन करने वाली इकाइयों के उत्पादन में मुश्किलें आएंगी वहीं दूसरी तरफ जो मजदूर वापस अपने गृह राज्य में पहुंच गए हैं वे भी वहां रोजगार बिना बैठे रहेंगे। ऐसी स्थिति में मुख्य समस्या लोगों की आजीविका की होगी कि आगे आने वाले समय में बिना काम के लोग अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। जो प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर दूर से वापस अपने घर आ गए हैं उनके आगे आने वाले कुछ महीनों तक वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। इसमें आवागमन की व्यवस्थाएं भी सामान्य होने में काफी समय लगेगा। वर्तमान तथा भविष्य में आजीविका से प्रभावित होने वाले मुद्दे पर एक जिले का विश्लेषण करें तो उसी से पूरे देश की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे देश के सभी 650 जिलों की स्थिति पर क्या प्रभाव हो सकता है ।कहीं ज्यादा कहीं कम लेकिन सभी जगह लोगों की आर्थिक स्थिति पर इस लॉकडाउन ने गहरा असर डाला है ।

अब समाज तथा सरकार की पहली प्राथमिकता बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। इसके लिए कुछ सरकारों को विशेष सुविधाएं तथा नीतिगत प्रावधान कर काम के प्रति मजदूरों का विश्वास बढ़ाकर काम के प्रति आकर्षित करना ताकि लोगों के अंदर का आत्मविश्वास पुनः वापिस आए, तभी भिन्न भिन्न सेक्टर में काम करने वाले लोगों को काम के साथ जोड़ पाएंगे । साथ ही इस लॉकडाउन ने यह सीख भी दी है, कि कैसे अलग–अलग सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को पंजीकृत करके उनकी सामाजिक आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी संरक्षण प्रदान करने के लिए नीतियों में परिवर्तन करें ताकि भविष्य में इस प्रकार से मजदूरों की भगदड़ की स्थिति में भी उनके अधिकारों का लाभ उनको मिल सके।मजदूरों के लिए बने तमाम श्रमिक कानूनों की खामियों में सुधार का यही सही अवसर है।

प्रस्तुत लेख में मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के पलायन करने वाले श्रमिकों ,फुटकर मजदूर और अलग–अलग क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

मध्य प्रदेश के उत्तर में राजस्थान और उत्तर प्रदेश प्रांत की सीमा से लगा हुआ चंबल नदी के किनारे मध्यप्रदेश का मुरैना जिला है जिसकी कुल आबादी 12.80 लाख है । जिले के 799 गांव में 2.50 लाख परिवार निवास करते हैं ।इनमें से 1.50 लाख परिवार पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं। 50 हजार परिवार नौकरी एवं स्वयं के कारोबार से आत्मनिर्भर हैं ।अब अगर पूरे जिले के रोजगार एवम् आजीविका का विश्लेषण किया जाय कि जिले में आजीविका के कौन कौन से सेक्टर है, तब पता लगेगा कि अलग–अलग सेक्टर में आजीविका के लिए लोग किस प्रकार काम करते हैं । जिसकी स्थिति के बारे में लॉक डाउन के तहत जब पता लगा तब पूरे देश में काम करने वाले लोग वापस घर लौटने लगे तथा जिले के अंदर भिन्न भिन्न कामों में काम करने वाले फुटकर मजदूरों का काम भी चला गया और वह भी घर बैठ गए। मोटे तौर पर देखा जाए तो हम इस लॉकडाउन के बाद अपनी रोजी रोटी खो चुके लोगों के बारे में समझ सकते हैं और उसी से यह अंदाज लगा सकते है कि देश के करोड़ों परिवारों की आजीविका किस प्रकार प्रभावित हुई है और वापस किस प्रकार आएगी।

श्रमिकों तथा प्रवासी मजदूरों के लिए तमाम नीतियों एवं कानूनों के होने के बावजूद भी, कोई भी नीति एवं कानून, 1 महीने से खुले में पड़े, दो समय की रोटी के लिए संघर्ष करने वाले, मजदूरों की मदद, किसी योजना या कानून के तहत नहीं कर सके। जो भी मदद मिली वह संबंधित राज्य सरकारों ने मानवीयता के आधार पर प्रदान की।

मुरैना जिले में असंगठित मजदूरों का विवरण जो कि अलग अलग क्षेत्रों में मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाते रहे हैं -

१.पलायन पर गए खेतिहर मजदूर

खेतिहर मजदूरों के लिए फरवरी मार्च का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। इस महीने में रवि की सभी फसलों की कटाई होती है। इस कटाई के मौसम में खेतिहर मजदूर अपने 5 से 7 सदस्यों वाले परिवार के लिए 6 कुंटल गेहूं मजदूरी के रूप में कमा कर लाते हैं। यह गेहूं सितंबर के महीने तक पर्याप्त हो जाता है। उसके बाद खरीफ की फसल से आगे के खाने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन के बाद जो मजदूरी करने गए थे वह बीच में ही वापस आ गए जो थोड़ी बहुत कमाई की थी वह या तो किराए भाड़े में खर्च हो गई या लॉकडाउन के दौरान कई दिनों तक इंतजार करना पड़ा और खरीद कर भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी उसमें खर्च हो गई, और मुरैना जिले के 1800 मजदूर घर खाली हाथ वापस आ गए। यह लोग मुरैना जिले के साथ-साथ आगरा तक मजदूरी करने गए थे इसलिए पैदल चलकर घर आने में सफल हो गए और एकता परिषद के साथियों ने उनको हर संभव सहयोग प्रदान किया जिला प्रशासन ने भी उनको घर पहुंचाने मैं मदद की। लगभग 2000 खेतिहर मजदूरों ने जिले के अंदर ही मजदूरी के लिए पलायन किया था ।

2. ईंट भट्ठा एवं खनिज में काम करने वाले मजदूर

मुरैना जिले में 42 ईट भट्टे हैं जिनमें 3000 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। 24 मार्च के बाद सभी भट्टे बंद हो गए मजदूरों का काम भी समाप्त हो गया जबकि कम से कम 2 महीने तक काम किया जा सकता था। इस प्रकार इन 3000 मजदूरों की 60 दिन की मजदूरी चली

गई जो उनके बरसात के दिनों में काम आती। इसी प्रकार जिले में अलग अलग खदानों के क्षेत्रों में 3500 लोगों का काम भी प्रभावित हुआ जिनके पास अभी कोई काम नहीं है।

3 फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूर

सरकारी रिकार्ड के अनुसार 30 फैक्ट्री बामोर के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित हैं। इन सभी फैक्ट्री में काम करने वाले 2000 से अधिक मजदूर मार्च के अंतिम सप्ताह से ही घर बैठे हैं जो बाहर के थे वह वापस अपने घर लौट चुके हैं। इसी प्रकार पूरे जिले में छोटे-छोटे 2 दर्जन से अधिक उद्योगों में काम करने वाले 2,000 से अधिक मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हैं हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को काम मिल जाए लेकिन तुरंत सभी लोगों को काम मिलेगा ऐसी कोई संभावना नहीं है।

4 खुदरा व्यापार से जुड़े मजदूर

छोटे-छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों,होटलों,आदि में जिले

में 10,000 से अधिक लोगों की लॉकडाउन के बाद सबकी छुट्टी कर दी गई है वे सब घर में बैठे हैं। आजीविका चलाने का उनके पास कोई साधन नहीं है।

5.घरेलू कामकाज में संलग्न मजदूर

घरेलू कामकाज के क्षेत्र में पूरे जिले में 2500 से अधिक लोग काम कर रहे थे जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से उनकी छुट्टी हो गई यह वह लोग हैं जो काम करने के बाद मिलने वाली मजदूरी से राशन खरीद कर घर लेकर जाते थे जिससे खाना बनता था।

6.फुटकर मजदूरी करने वाले मजदूर

अलग–अलग क्षेत्रों में जिले में लगभग 15000 से अधिक लोग रोजाना की मजदूरी के हिसाब से काम करते थे अभी इनके पास कोई काम नहीं है।

7. जिले के बाहर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर

जिले के 3000 से अधिक लोग जिले के बाहर अलग–अलग सेक्टरों में जैसे पत्थर के टाइल्स लगाना,कारीगरीकरना,मशीन
चलाना,ड्राइवर,कैटरिंगआदि क्षेत्रों में मजदूरी करते थे उनमें से लगभग 80 प्रतिशत लोग वापस जिले में आ चुके हैं जिनके पास आगे की रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है।

जिले में लगभग 50,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है जहां मजदूरी करके अपनी आजीविका चला रहे थे वहां से छोड़ कर वापस आ चुके हैं। जो कुछ कमाया था वह खर्च करके खा लिया । इनकी कमाई से 2.50 लाख लोगों की आजीविका चलती थी । बेरोजगार हुए ये 50000 परिवार जिले के कुल परिवारों के 20 प्रतिशत है जो पूरी तरह से हाशिए पर खड़े हैं इनको आगे आने वाले कम से कम 6 महीने के लिए आजीविका की अत्यंत जरूरत है जिस पर समाज, सरकार और राजनीतिक दल, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है।

इस प्रकार पूरे देश में 4 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनकी आजीविका पूरी तरह से प्रभावित हुई है मजदूरी के अलावा जिनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है इनके पूरे परिवार को जोड़ा जाए तो यह संख्या 4 करोड़ परिवारों की 20 करोड़ की आबादी को प्रभावित करने वाली है। यही स्थिति देश के सभी 650 जिलों की है कहीं कम कहीं अधिक समस्या है लेकिन भविष्य में काम को लेकर सभी की चिंताएं हैं कि आगे अपने परिवार की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे । इस आपात स्थिति में श्रम कानून एवं सभी कल्याण की नीतियों की जमीनी हकीकत को भी बेनकाब कर दिया है तथा भविष्य में इन मेहनतकश लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए पूरे देश और सरकारों के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं ।

5 हजार मजदूर बेरोजगार,

पहाड़गढ़ में सहरिया आदिवासियों को बाहर से गांव आने के बाद नही मिला रोजगार।

– उदयभान सिंह जी मुरैना

जिला मुरैना–लॉकडाउन में अन्य प्रांतों से मुरैना जिले में आये मजदूरों को बीते दिन से पंचायत स्तर पर काम नही मिला है जबकि प्रशाशन मनरेगा में काम उपलब्ध कराने के दावे कर रहा है। इन हालातों के बीच सहरिया आदिवासी मजदूर, सेवाभावी लोगों के आटा दाल व चावल

के पैकेटों से अपने परिवार का पेट पालन करने को मजबूर हैं। मनदेगा में काम को लेकर जनपद पंचायत के अफसरों का कहना है कि अभी बजट आयेगा। तब नये काम खोले जायेंगें। पहाड़गढ़ जनपद के कन्हार , जड़ेरु, मरा, मानपुर, बघेबर, बहराई धोबिनी, खड़रियापुरा आदि ऐसे गांव हैं जहां सहरिया आदिवासी बिरादरी के श्रमिक लोकडाउन के कारण बैंगलोर पुणे, राजस्थान आदि प्रांतों से अपने गांव व घरों में 15 दिन पहिले आ गये हैं। लेकिन सवा महीने से मजदूरी बंद होने के कारण उनके पास उदरपूर्ति के लिये पैसे नही हैं। मजदूरी कर पेट पालने में ये मेहनतकश यदि कही काम करने का मन बनाये ंतो ग्राम पंचायतों ने अभी तक मनरेगा के तहत नये काम नही खोले हैं। इस हाल में पहाड़गढ़, कैलारस, सबलगढ़ व दिमनी अंचल के 5000 से ज्यादा श्रमिक इन दिनों बिना काम के घर बैठे हुये हैं।

एकता परिशद जिला मुरैना के जिला समन्यक उदयभान सिंह जो कि वंचितों के बीच राहत सामग्री का पेकेट वितरण कर एक माह के भोजन के भोजन की व्यवस्थाये सुनिश्चित की हैं, उन्होने वहां का जायजा लेकर बताया कि पहाड़गढ़ जनपद के मानपुर गांव के 67 सहरिया आदिवासी परिवार, बहराई में 82, बघेबर में 95 , कन्हार कुन्दनपुरा में 90 व मरा में 157 परिवारों के लोग घरों व टपरों में रहकर काम मिलने की आस लगाये हुये हैं।

राहत कार्यों के इंतजार में पलायन न हो जाए शुरू

20 हजार से भी अधिक पलायन से वापस आए मजदूर परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट।

– दौलतराम गौड़ कराहल

कराहल, श्योपुर। *देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार की तलाश में गए 20 हजार से भी अधिक मजदूर परिवार वापस लॉकडाउन के कारण वापस लौट आए हैं। पलायन से वापस लौटे इन परिवारों के आगे अब रोजी-रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। तेंदूपत्ता तुड़ाई और वनउपज संग्रहण से आस खत्म हो जाने के बाद अब मजदूरों को मनरेगा से आस है, लेकिन जिला प्रशासन की ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिखाई दे रही जिससे लगे की मजूदरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए गांवों में राहत कार्य चलाए जाएंगे।*

मई-जून में कराहल विकासखंड से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन शुरू हो जाता है। इस पलायन को रोकने के लिए सरकार ने मनरेगा से राहत कार्य शुरु करती हैं, जिसमें तालाब गहरीकरण, नदियों पर स्टाप डैम बनाना इत्यादि काम को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि रोजगार

के साथ-साथ पानी के संसाधन अधिक से अधिक उपलब्ध हो सके। इस बार प्रशासन की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिससे लगे की जिले में मनरेगा से राहत कार्य शुरु किए जा रहे हैं। अगर गांवों में राहत कार्य शुरु नहीं हुए तो मजदूरों के आगे भूखे मरने की स्थिति निर्मित होना तय है।

बढ़ रही हैं पलायन की छटपटाहट

भले ही लॉकडाउन लगा हो, लेकिन कराहल विकासखंड जैसे क्षेत्र में रोजगार के अभाव में आदिवासियों में पलायन की छटपटाहट होने लगी हैं। स्थानीय स्तर पर काम नहीं मिलने से मजदूर लॉकडाउन खुलते ही फिर पलायन कर सकते हैं। उधर पड़ौसी जिले राजस्थान के सवाई माधौपुर में मनरेगा से तालाब गहरीकरण, नए तालाब बनाने, स्टापडैम इत्यादि काम शुरु किए जा चुके हैं। इसलिए भी मजूदरों के मन में पलायन की छटपटाहट बढ़ रही हैं। यह छटपटाहट तेंदूपत्ता तुड़ाई बंद होने के बाद ठेकेदार वनउपज संग्रहण महुआ की बिक्री नहीं होने से भी बढ़ी है।

श्योपुर के प्रवासी मजदूरों को भारी पडा लॉकडाउन
एक एक हजार रुपये किराया देकर जैसलमेर से श्योपुर पहुँचे 563 मजदूर

– जयसिंह भाई श्योपुर

जिला श्योपुर– आये थे हरिभजन.को ओटन लगे कपास यह कहावत श्योपुर के प्रवासी मजदूरों पर खरी उतर रही है श्योपुर से तो यह सोच कर प्रवास पर गये थे कि भविष्य के लिए कुछ पैसा जोड़कर लायेंगे ।

कमाया सो खाने में गंवाया
अब उधार लेकर हुए वापिस
राजस्थान सरकार के
अधिकारियों ने भी खडे
किये हाथ
प्रायवेट बसों को कई लाख
रुपये किराया देकर आये
मजदूर

पर होनी को कुछ और ही मंजूर था कुछ दिन सब कुछ ठीक चला पर फिर आया कोराना का कहर और फिर उससे बचने को घोषित लॉकडाउन बिना यह सोचे कि काम बंद होने पर घर से दूर बैठे इन मजदूरों का क्या होगा यह कदम इन पर दुर्भाग्य

बनकर टूटा कुछ दिन तो बचे पैसों से काम चलाया फिर राशनपानी का संकट पैदा हो गया तब संकट मोचन के रूप में उन्हें नजर आई **एकता परिषद और उन्होंने महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक जयसिंह भाई से संपर्क कर मदद.की गुहार लगाई** और उन्होंने स्थानीय संपर्क और प्रशासन के माध्यम से उनके राशनपानी की व्यवस्था करवाई पर जगह जगह अस्थायी ठिकाना बनाकर रह रहे मजदूरों का बस यही आग्रह रहता था कि हमें अपने गांव पहुंचाओ जयसिंह भाई के अथक प्रयासों तथा मप्र व राजस्थान सरकार की सदिच्छा से इन मजदूरों के अपने घरों पर आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ और श्योपुर सहित विभिन्न जिलों के लगभग 5000 मजदूर अपने घर पहुंच गये

पर अभी भी जैसलमेर मे 700 मजदूर आने को तैयार बैठे थे कि राजस्थान सरकार ने अपने हाथ वापस खींच लिये 3 दिन तक इन मजदूरों ने बसों का इंतजार किया पर बसें इन्हें लेने नहीं पहुंची इसपर उन्होंने अपने मददगार जयसिंह भाई को इस बात की जानकारी दी तथा पैदल कलेक्टर कार्यालय की और चल दिये उधर जयसिंह भाई ने श्योपुर कलेक्टर को इस बात की जानकारी दी जिन्होंने इस बारे में कार्यवाही का आश्वासन दिया उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी एक पत्र इस जानकारी के साथ लिखा तथा उनसे इन मजदूरों की वापसी के लिये मदद को कहाजयसिंह भाई ने सी एम हाउस के कन्ट्रोल रूम को सम्हाल रहे ए आई सी

सी सदस्य संजय बाफना जी से भी बात की जिन्होंने मदद का आश्वासन दिया तथा मजदूरों के नंबर लिए लेकिन स्थानीयप्रशासन ने उन्हें भी गुमराह कर दिया कि हमने बसे कर दी है ये नही बताया कि किराये की बस की हैं, जिसकी सूचना जयसिंह भाई द्बारा संजय बाफना जी को भी दी गई।

जिस सरकार ने हजारो मजदूरों को उनके घर कई राज्यो में पहुचाया आखिरी में स्थानीय कुछ अधिकारियों ने उनकी थू थू कराने में कोई कसर नही छोड़ी।

मरता क्या न करता

जयसिंह जादोन की पहल द्वारा स्थानीय सहयोगियों के माध्यम से सूखा राशन उपलब्ध हो जाने के कारण बचे कुछ पैसे बस किराए के रूप मे देने को तैयार हो गये. जिनके पास पैसे नहीं बचे थे उन्होंने साथियों से उधार लेकर किराया अदा किया लगातार बढ रहे लॉकडाउन के कारण वे जैसे भी हो अपने घर पहुंचना चाहते थे। इसलिये एक एक हजार रुपये प्रति यात्री किराया देकर जैसलमेर से श्योपुर पहुॅचे हैं।

पलायन से लौटे मजदूरों के लिये काम की तलाश....

–श्री डोंगर शर्मा ग्वालियर

जिला ग्वालियर–देशव्यापी बन्द के बीच समाज के उस तबके को वापस अपने घर पहुॅचाने का जो सरकारी और गैरसरकारी प्रयास किया जा रहा है, वह सराहनीय है। धीरे–धीरे लोग अपने गांव–घर पहुॅचने लगे हैं और सरकार द्वारा दिये गये निर्देषों का पालन भी कर रहे हैं। कुछेक जरुरतमंद परिवारों को छोड़ दें तो अधिकांष परिवारों को सरकार की उन विषेष योजनाओं का लाभ मिल रहा है जिसे कोरोना महामारी के कारण प्रारंभ किया गया है।

इन सारे सकारात्मक प्रयासों के बावजूद एक समस्या जो अभी भी विकराल रुप में समाज के वंचित वर्ग के सामने खड़ा है, वह है भूख मिटाने की समस्या। कोरोना संक्रमण के कारण पलायन पर गये मजदूर जहां काम कर रहे थे उसे बन्द कर दिया गया जिसके कारण मजदूरों को वापस अपने घर लौटना पड़ा। अब गांव में आकर अगर उन्हें काम नहीं मिला तो वे भूखे रहने के लिये बाध्य होंगे। इस परिस्थिति में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने कायक्षेत्र के गांवों में घर–घर जाकर सम्पर्क किया गया और यह जानने का प्रयास किया गया कि लोग काम करने के लिये तैयार हैं या नहीं। ऐसे लोग जो मजदूरी करने के लिये तैयार हैं, उनकी सूची बनाई गई और संबंधित पंचायतों में दिया गया ताकि मनरेगा के तहत काम षुरु किया जा सके। अब तक 10 पंचायतों में 596 लोगों की सूची दी गई है और लगतार पंचायतों पर इस बात के लिये दबाव बनाया जा रहा है कि लोगों को काम दिया जाये। इसके अलावा ग्वालियर के अन्य पंचायतों में भी सूची बनाने की प्रक्रिया जारी है।

3 मई 2020 को ग्वालियर जिले के रुद्रपुरा गांव में रह रहे 30 आदिवासी परिवारों का स्वास्थ्य जांच करवाया गया। संगठन के अनुरोध पर चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा रुद्रपुरा गांव जा कर सभी सहरिया परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, उन्हें कोरोना वायरस से बचने का उपाय बताया गया और अपना हेल्पलाईन नम्बर दे कर कहा गया कि –''कोरोना महामारी से डरने की बिल्कुल जरुरत नहीं, केवल घर में रहकर अपना ध्यान रखें। भीड़ वाले इलाके में जाने से पहले मास्क जरुर पहने, घर लौटकर जुता,चप्पल बाहर उतारें और कपड़ा भी धोने के लिये डालें। हाथ–पैर ठीक से धो कर ही घर का कोई काम करें और जरुरत पड़ने पर तत्काल फोन करें।''

मनरेगा कार्य के लिये सूची कर रहे तैयार ताकि मिल सके काम .....

–चन्द्रभान सिंह अशोक नगर

अशोकनगर जिले *के ग्राम कुरवासा और जाखलोन में लोगों को नियमानुसार हाथ धोने का महत्व बतलाया गया और कुछ लोगों के साथ सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुये बैठक किया गया। बैठक में मजदूरी धोजगार के संबंध में चर्चा की गई। यह तय हुआ कि लोगों को कुछ काम देना जरुरी है वरना लोग भूखे रहने को मजबूर हो जायेंगे क्योंकि पलायन पर जाने के बाद भी काम मिल नहीं पाया और खाली हाथ वापस आना पड़ा। इस स्थिति में अगर स्थानीय स्तर पर कुछ काम नहीं मिला तो वंचित वर्ग के हाथ में कुछ नहीं होगा। इस प्रकार गांव में काम करने के इच्छुक मजदूरों की एक सूची बनाने का काम प्रारंभ किया गया है जिसे संबंधित पंचायत तथा रोजगार सहायक को दिया जायेगा ताकि जल्द से जल्द पलायन से गांव लौटे मजदूरों तथा अन्य जरुरतमंद लोगों को काम दिया जा सके। अन्त में, लोगों को यह भी बताया गया कि ग्रीन जोन में आ जाने से यह बिल्कुल न सोचे कि कोरोना महामारी की समस्या समाप्त हो गई। अगर गांव के लोग बिल्कुल सावधान नहीं रहे और षासन–प्रषाासन द्वारा दिये गये निर्देषों का अक्षरषः पालन नहीं किये तो कोरोना वायरस फैल सकता है।*

जिले में मनरेगा काम हों शिरु, मुरैना कलेक्टर के साथ मीटिंग में रखी मांग।

कलेक्टर महोदया ने कहा शीघ्र चालू होगें काम

– प्रफुल्ल श्रीवास्तव मुरैना

जिला मूरैना –लॉकडाउन में अन्य प्रांतों से मुरैना जिले में आये मजदूरों को मनरेगा का काम देने और खाद्धान राशन की व्यवस्था को ले कर एकता परिषद जिला मुरैना के समन्वयक श्री उदयभान सिंह एवं महात्मा गांधी सेवा आश्रम के प्रबंधक श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी ने जिला कलेक्टर सुश्री प्रियंकादास जी के चेम्बर में जाकर मुलाकात की और मनरेगा के काम खोलने की मांग रखी। उदयभान सिंह जी ने बताया कि पहाड़गढ़ जनपद के कन्हार , जड़ेरु, मरा, मानपुर, बघेबर, बहराई धोबिनी, खड़रियापुरा आदि ऐसे गांव हैं जहां सहरिया आदिवासी बिरादरी के श्रमिक लोकडाउन के कारण बैंगलोर पुणे, राजस्थान आदि प्रांतों से अपने गांव व घरों में 15 दिन पहिले आ गये हैं। लेकिन सवा महीने से मजदूरी बंद होने के कारण उनके पास उदरपूर्ति के लिये पैसे नही हैं। मजदूरी कर पेट पालने में ये मेहनतकश यदि कही काम करने का मन बनाये तो ग्राम पंचायतों ने अभी तक मनरेगा के तहत नये काम नही खोले हैं। इस हाल में पहाड़गढ़, कैलारस, सबलगढ़ व दिमनी अंचल के 5000 से ज्यादा श्रमिक इन दिनों बिना काम के घर बैठे हुये हैं। कलेक्टर महोदया जी ने मनरेगा कार्य शीघ्र चालू कराने का आश्वाशन दिया है।

एकता परिषद कार्यालय गांधी भवन भोपाल टीम द्वारा जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने का कार्य प्रारंभ .....

स्त्रोत – कोरोना रिस्पोंस समूह

भोपाल *–भोपाल के कोरोना फाइटर्स के लिए शुरू की गई मध्यान्ह भोजन व्यवस्था..... कई फाइटर्स पुलिस, स्वास्थ्य, सफाई कर्मी मित्रों ने किया मध्यान भोजन ।*

घर घर जाकर कर रहे निराश्रित और दिव्यागों की मदद.....

जिला सागर–सागर जिले के मालथौन तहसील के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में कई लोग ऐसे सामने आए जिसमें बूढ़े मां बाप को अलग करके खाने कमानेचले गये हैं। ऐसी भारी विपदा ये परिवार खाने कमाने के लिए मोहताज है।ऐसे कई परिवारों को सूचीबद्ध कर उन्हे खाद्धान राशन दिलाने के लिये एकता परिषद सागर की टीम घर घर जाकर सर्वे कर मदद दिलाने का कार्य कर रही है।

2. छत्तीसगढ़

'आज भी खरे हैं तालाब': छत्तीसगढ़ सरकार की पहल....

स्त्रोत– श्री रघुवीर दास

जिला सरगुजा –छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक सोची–समझी रणनीति के तहत बरसात से पूर्व प्रदेष के गरीब, वंचित मजदूरों के लिये बड़े पैमाने पर तालाब निर्माण का काम प्रारंभ किया गया है। इस कार्य से पलायन से लौटे मजदूरों के साथ–साथ गांव के समस्त गरीब, वंचित समुदायों को भी लाभ मिला है। संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्षेत्र के लोगों के लिये संबंधित पंचायतों में आवेदन दिया गया है ताकि मनरेगा के तहत लोगों को काम दिया जा सके। इसी क्रम में सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के बद्रीकाश्रम तथा फूलचुही गांव में तालाब निर्माण का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कोरबा जिले के पौड़ीउपरोड़ा तथा कोरबा ब्लॉक के कुम्हारी दर्री, चन्द्रौटी, मल्दा व देवपहरी गांव में भी तालाब निर्माण का काम प्रारंभ किया गया है जिससे संगठन के लगभग 200 सदस्यों को काम करने अवसर

मिला है जो इस कोरोना संकट के काल में बड़ी राहत है।इसके अलावा मनरेगा के तहत ही अन्य प्रकार के काम भी किसे जा रहे हैं जैसे सरगुजा जिले के सलका गांव को पत्थर से घेरने का काम किया जा रहा है जिसमें एकता परिषद की कार्यकर्ता अमर भाई के सहयोग से संगठन के सदस्यों को जोड़ा गया हैं।

सावधानी से कोरोना को हराना है.....

केन्द्र और प्रदेश सरकार के निदेर्षो का पालन करने वाले नागरिकों को देख कर इस बात का विश्वास और गहरा हो जाता है कि कोरोना को जल्दी ही हिन्दुस्तान से विदा लेना होगा। छत्तीसगढ़ के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक का एक गांव है चन्द्रौटी। इसी गांव में एकता परिषद की महिला कार्यकर्ता, निर्मला कुजुर के द्वारा गांव के लोगों को पानी भरने के स्थान पर लगभग एक–एक मीटर पर गोलाकार बनाकर खड़े होना सीखाया गया। अब गांव के लोग पानी भरने के लिये बनाये गये गोले में ही खड़े होते हैं। प्रदेष के गांव–गांव में इस प्रकार का प्रयास होना चाहिये ताकि लोग स्वयं ही सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग और नियमानुसार हाथ धोने के महत्व को समझ सकें।

ग्राम पंचायत भूरसुदा में लॉक डाउन के दौरान पलायन में फँसे परिवारो के बच्चों एवम बुजुर्गो .व जरूरतमंदो को खाद्य सामग्री.साबुन. व आवश्यक सामान प्रयोग आश्रम एंव एकता परिषद तिल्दा द्वारा वितरण किया गया

3. ओड़िसा

जरुरतमंदों के लिये जारी है राहत सामग्री वितरण कार्य.....

स्त्रोत– सुश्री रोशनआरा एवं स्नेहलता

- ***खुर्धा जिले*** *के कुंजुरु तथा निराद्रीप्रसाद पंचायत में स्थनीय सरपंच की उपस्थिति में लोगों को राहत सामग्री वितरित की गई।*
- *एकता परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कुंजरी पंचायत के कोरनटाईन सेन्टर का भ्रमण किया गया जहां पलायन से लौट कर आये 312 लोगों को रखा गया है।*
- ***कालाहांडी जिले*** *के गोंड़ापदर गांव में संगठन की महिला कार्यकर्ता प्रमोदिनी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पलायन संबंधी जानकारी इकट्ठा करके फार्म भरने के साथ–साथ वन अधिकार अधिनियम के तहत जिन लोगों को व्यक्तिगत अधिकार–पत्र मिला है, उन्हें मनरेगा से जोड़ कर भूमि विकास की योजना बनाई गई।*
- *एकता परिषद के प्रयास से कालाहांडी जिले के मनिकेरा पंचायत के सुलुसुरु गांव में मनरेगा के तहत भूमि विकास का काम प्रारंभ किया गया। संगठन के साथियों को मजदूरी मिलने से वे काफी खुष हैं।*
- *कालाहांडी जिले के उपरनुवागांव में युवतियों के लिये एक प्रषिक्षण आयोजित*

किया गया जिसमें लड़कियों को कोरोना महामारी के बारे में विस्तार से बताया गया। आने वाले कम से कम छः महीने तक क्या–क्या सावधानियां बरतनी है, यह भी बताया गया। ठीक से हाथ धोने से लेकर, योगाभ्यास, भोजन में ध्यान देने योग्य बाते, लोगों को मदद करने जैसे कई बातों पर चर्चा की गई।

4. असम

पलायन का दर्द....

–श्रीडिम्बेश्वरनाथ एंव नयनतारा जी

डिबरुगढ़ जिले के डिमो और खुरांग गांव के श्रमिक हर साल ठेकेदार के साथ जोरहट जिले के मोरियानी षहर में काम करने आते हैं। इस वर्ष भी 5 लोग उसी ठेकेदार के साथ काम करने आये लेकिन जैसे ही देष में लॉकडाउन की घोषणा हुई, ठेकेदार श्रमिकों को छोड़ कर भाग गया और अपना मोबाईल बन्द कर लिया। अपने गांव से 150 किलोमीटर दूर काम करने वाले इन 5 मजदूरों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ दिन तो आस–पास के लोगों ने खाना खिलाया लेकिन अनिष्चितता के इस दौर में, मजदूरों का काम कबतक बन्द रहेगा, ये भी स्पष्ट नहीं था। ऐसे में सभी 5 मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़े क्योंकि न तो इन लोगों के पास काम था और न खाने के लिये अनाज। ऐसी स्थिति में एक ही आसरा था अपना गांव, अपना घर। रास्ते में एकता परिषद के कार्यकर्ता, जो जोरहट जिले में काम करते हैं, से इन मजदूरों की मुलाकात हुई तब सारी जानकारी मिली। संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा इस सभी लोगों को भोजन कराया गया और वापस घर भेजने की व्यवस्था की गई।

संगठन के माध्यम से असम के कई गांवों में राहत कार्य......

असम एकता परिषद ने खाद्य सामग्री बांटी

असम राज्य में पिछले 3–4 दिनों से राहत सामग्री वितरण का काम तेजी से किया जा रहा है। असम के तिनसुकिया, धेमाजी, जोरहट, कामरुप रुरल और धुबरी जिले के 7 ब्लॉक के 28 गांवों में 110 अतिगरीब परिवारों को राषन वितरित किया गया। राषन वितरण के दौरान सरकार के नियमों का पूर्णतः पालन किया गया। लोगों को खड़े होने के लिये गोलाकार बनाया गया, राहत सामग्री लेने से पूर्व हाथ धुलाया गया। इसी प्रकार रतनपुर,पानीखेती, बीटूतरी और अम्बरी गॉव के 50 से भी अधिक प्रवासी मजदूर परिवारोंको चावल,तेल आलू और नमक आदि का वितरण किया गया समुदाय में कोरोना संक्रमण से बचने के लिये मास्क और सेनिटाइजर का भी वितरण किया गया।

5. झारखंड

एकता परिषद झारखंड टीम ने उपलब्ध कराई खाद्ध सामग्री

स्रोत– कोरोना रिस्पोंस समूह

जिला बगोदर – बगोदर प्रखंड के अटका में एकता परिषद बगोदर इकाई द्वारा खाद्ध सामग्री का वितरण किया गया हैश इस दौरान एकता परिषद के वरिष्ठ साथी रामस्वरुप तिवारी ने बताया कि अटका में जरुरत मंदो के बीच 10 किलो चावल,2 किलो दाल, 2 किलो आलू, नमक आदि सामग्री 50 परिवारों को वितरित की गई। और बीमारी के संक्रमण से बचने के लिये 'शोशल डिस्टेसिंग का पालन करना बताया गया।

6. तिलगांना

कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए एन.वाय.पी. सदस्यो ने शुरु किया राहत अभियान

अपने आसपास किसी को भी भूखा न सोने दें – डा.एस.एन.सुब्बाराव

स्रोत – कोरोना रिस्पोंस समूह

नई दिल्ली– प्रखर समाज सेवी एवं गांधीवादी डा. एस. एन. सुब्बाराव जी द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा योजना **(NYP)** इकाई के समस्त युवाओं को मोबाइल कॉन्फ्रेस में संबोधित करते हुये कहा कि इस समय देश में संकट का समय चल रहा है, अपने आस पास किसी को भी भूखा न सोने दे। उनकी सेवा करें। बाहर दूसरे राज्यों से फसे हुए मजदूरों की सहायता करें। जिस तरह भी हो लोगों की सहायता करें। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और घर पर ही रहकर सर्वधर्म प्रार्थना करें।

देश के विभिन्न राज्यों में NYP यूनिटे अपने स्वयंसेवको के माध्यम से कोरोनावायरस से बचाव हेतु मदद एंव जागरूकता अभियान चला रही हैं। इकाई के सदस्यों को जागरूकता हेतु प्रतिदिन अलग अलग कार्य टास्क के रूप में दिये जाते हैं जिसके माध्यम से सदस्यो द्वारा लोगो को जागरूक किया जाता है । जरुरतमंद लोगों के लिये तैयार भोजन या सूखा राशन सामग्री, पशु पक्षी के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना , सेल्फी विथ मास्क अभियान , विडियो संदेश बनाना स्लोगन व कविता लेखन करना एंव अपने घरो के आस पास व मुहल्ले एंव गांवों में साफ सफाई अभियान चलाना आदि कार्य सदस्यो द्वारा किये जा रहे हैं।

NYP यूनिट तिलगांना और एकता परिषद तिलंगाना द्वारा संयुक्त राहत अभियान के तहत उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आन्ध्रप्रदेश के प्रवासी मजदूरों के लिये खाद्य राहत सामग्री वितरण कार्य किया गया।

पशुओं के लिये हरी घास, सब्जियाँ एंव पक्षियों के लिये दाना पानी

बैतूल में कोरोना चेतना संग सुब्बराव जी प्रणीत राष्ट्रीय युवा योजना इकाई का पशु-पक्षी दाना-पानी अभियान

आप श्रमिक वर्ग / मज़दूरों को उनके निर्धारित अधिकार दिलानें में कैसे मदद कर सकते हैं ?

भारत में श्रमिक वर्ग / मज़दूरों के हितों के रक्षा के लिये कई कानून और नीतियां बनाई गयी हैं किन्तु इसका वास्तविक क्रियान्वयन अब तक आधा अधूरा ही रहा है। एकता परिषद और अन्य संगठनों के साथियों को इन कानूनों, नीतियों और श्रम संस्थानों के माध्यम से श्रमिक वर्ग / मज़दूरों के अधिकारों के लिये सामने आना चाहिये।

- अपनें क्षेत्र में श्रमिक वर्ग / मज़दूरों को निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी दिलाने का प्रयास करें।
- कहीं भी बाल श्रमिक / मज़दूर हों तो इसकी सूचना श्रम अधिकारी को अवश्य देना चाहिये।
- पलायन करने वाले श्रमिक वर्ग / मज़दूरों का पंजीयन, स्थानीय श्रम अधिकारी के स्तर पर अवश्य करवायें। इस पंजीयन के आधार पर निर्धारित सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना सरकार की जवाबदेही है।
- अपनें क्षेत्र में कहीं भी बंधुआ मज़दूर की सूचना मिले तो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर उसे मुक्त और पुनर्वास करवानें मे सहयोग करें।
- कई राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको संबंधित पदाधिकारी से मिलकर अपनें क्षेत्र में मनरेगा कार्य शुरू करवाना चाहिये। वास्तव में मनरेगा का सार्थक प्रयोग तालाब / पोखर / नहर / कुआँ और छोटे जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण के लिये अधिक होना चाहिये। आप इस कार्य को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- हरेक राज्य में कृषि, निर्माण और इंडस्ट्री क्षेत्र के श्रमिकों / मज़दूरों के लिये योजनायें संचालित की जाती हैं। हमें इनकी जानकारी संबंधित लोगों तक पहुँचानें में जुट जाना चाहिये।
- श्रमिक वर्ग / मज़दूरों के कार्य संबंधी विवादों के लिये कई राज्यों में पृथक कोर्ट की व्यवस्था है। हमें संबंधित प्रकरणों के लिये प्रभावित वर्ग को उपयुक्त वक़ीलों के माध्यम से मदद करना चाहिये।

उपरोक्त सरल तरीकों से हम सब मिलकर श्रमिक वर्ग / मज़दूरों को व्यक्तिगत और संगठनात्मक रूप से मदद कर सकते हैं।

एकता परिषद्, संसाधन केन्द्र, पुरानी छावनी थाने के पास, ए.बी. रोड पुरानी छावनी ग्वालियर,सम्पर्क-9993592425
Contact Persons : Ran Singh Parmar 9993592425, Email: mgsa.india@gmail.com ,
www.mahatmagandhisevaashram.org, www.ektaparishad.org